

72/2023

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशयत्य जज

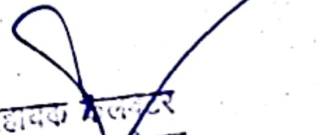
11/3/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनी के अधिवक्ता उपस्थित। विप्राथी संख्या 1 से 4 व 6 एवं 9 से 15 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्राथी एकपक्षीय। विप्राथी संख्या 1,3 व 6,9 को छोड़ते हुए शेष विप्राथी की तरफ से लम्बे समय से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थनी/वादीनी माफिक अनुतोष पाने की हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नहीं बढ़े। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्वष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थनी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढ़ेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थनी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थनी के पक्ष में बनते है।

लिहाजा प्रार्थनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.3.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक जज
(S.D.O.) जयपुर